



न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली दो क्रूज़ मिसाइलों का किया परीक्षण

सियोल। उत्तर कोरिया ने बुधवार को पूर्वी सागर में पनडुब्बी से दागी जाने वाली दो प्रकार की रणनीतिक क्रूज़ मिसाइलों का परीक्षण किया। सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

केसीएनए के हवाले से दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप ने बताया कि, इस परीक्षण का उद्देश्य पानी के भीतर संचालित होने वाली हथियार प्रणालियों की मौजूदा तैयारियों का आकलन करना था। एजेंसी ने कहा कि इससे नौसेना की रणनीतिक अभियानों को अंजाम देने की क्षमता का परीक्षण हुआ और देश के निवारक हथियारों की विश्वसनीयता तथा प्रभावशीलता भी प्रदर्शित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल परीक्षण की निगरानी सतारूद्ध वर्कर्स पार्टी आफ कोरिया के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य किम जोंग-सिक, मिसाइल प्रशासन के महानिदेशक जांग चांग-हा और नौसेना की पनडुब्बी आधारित हथियार प्रणालियों से जुड़े इंजीनियरों ने की। यह घटनाक्रम उत्तर कोरिया की ओर से सोमवार को प्योंगयांग क्षेत्र से पूर्वी सागर की दिशा में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को कहा था कि उस परीक्षण का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण मुख्य घटक को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए किए गए शोध की सफलता की पुष्टि करना था। हालिया क्रूज़ मिसाइल परीक्षण के साथ उत्तर कोरिया ने अपनी पनडुब्बी आधारित हथियार प्रणालियों की तैयारियों को परखने पर जोर दिया है। हालांकि, केसीएनए की रिपोर्ट में मिसाइलों की मारक दूरी, परीक्षण के विस्तृत तकनीकी परिणामों और इस्तेमाल की गई पनडुब्बी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती: एशियाई देश मिलकर बनाएंगे आपातकालीन तेल भंडार



मनीला। पश्चिम एशिया में बढ़ते वैश्विक तनाव और आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच एशियाई देशों ने एकजुट होकर आपातकालीन तेल भंडार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी (एजेडईसी) की मंत्रिस्तरीय बैठक में जापान के नेतृत्व में सदस्य देशों ने तेल सुरक्षा को मजबूत करने की संयुक्त कार्ययोजना पर सहमति जाहिर की है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य संकट के समय तेल भंडारण ढांचे का साझा उपयोग करना और बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए मिलकर रणनीतिक भंडार से ईंधन जारी करना है। इस नई रणनीति का एक प्रमुख पहलु यह है कि एशियाई देश आपातकालीन तेल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय सहयोग को भी निरंतर आगे बढ़ाते रहे। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन, अमेरिका और जापान जैसे प्रमुख देशों के तेल भंडारों के आंकड़ों का आकलन करते समय सरकारी रणनीतिक भंडार और कारोबारी भंडार के अंतर को समझना आवश्यक है। जापान की इस पहल का मुख्य ध्येय आपात स्थितियों में सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति के झटकों से सुरक्षित रखना है।

अजरबैजान में हिजाब प्रतिबंध पर बवाल, छात्रों व सरकार में टकराव, छात्रों और शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, कई गिरफ्तारियां भी हुईं

बाकु। मध्य एशियाई मुस्लिम देश में इन दिनों कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार ने देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में तय युनिफार्म के अनुरूप न होने वाले या शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ माने जाने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है। हालांकि इस आदेश में हिजाब का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन कई स्कूलों ने इस नियम को हिजाब पहनने वाली छात्राओं पर लागू कर दिया है, जिससे मुस्लिम बहुल इस देश में हंगामा मच गया है। अजरबैजान की करीब 96 फीसदी आबादी मुस्लिम है। देश में शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद अजरबैजान का संवैधानिक ढांचा धर्म और राज्य को अलग रखने के सिद्धांत पर आधारित है। सरकार के इस कदम ने धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार और राज्य की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजरबैजान का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष बताता है और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है, लेकिन साथ ही शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष रखने का प्रावधान भी करता है। इसी आधार पर 21 सितंबर को कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत सरकारी सामान्य शिक्षा संस्थानों के छात्रों की युनिफार्म में बदलाव किया गया, जिसका मकसद एक ऐसा ड्रेस कोड लागू करना था जो देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को दर्शाता हो।

नईदुनिया

यमन के राष्ट्रपति भवन पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, चार की मौत

अदन। यमन के अदन शहर में हूती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन परिसर पर पांच बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। घटना के समय प्रधानमंत्री शाया मोहसेन अल-जिंदानी और सरकार के कई मंत्री परिसर में मौजूद थे। सूचना मंत्रालय के अनुसार, सभी सुरक्षित हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने अदन में सऊदी अरब के सैन्य अभियान मुख्यालय को निशाना बनाया। हूती मीडिया ने हथियारों के भंडार पर हमला करने की बात भी कही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की

अंतरिम राजधानी है। इस हमले के बाद देश में जारी संघर्ष और बढ़ने की आशंका है।

सऊदी अरब यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है और हूतियों के खिलाफ लड़ रही सरकारी सेनाओं को हवाई सहायता देता है। वहीं, ईरान पर हूती विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए हुए हैं।

ब्रिटेन की संस्था कॉम्प्लिक्ट आमॉमेंट रिसर्च की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, हूती विद्रोही चीन से मंगाए गए पुर्जों को मदद से नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में

कहा गया है कि विद्रोही ईरान में डिजाइन की गई खैबर शिकन मिसाइल जैसी मिसाइल तैयार करना चाहते हैं। इसकी मारक क्षमता करीब 1,500 किलोमीटर बताई गई है।

यदि हूती ऐसी मिसाइल बनाने में सफल होते हैं, तो वे सऊदी अरब के साथ इजराइल को भी अधिक सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम हो सकते हैं। ईरान ने 9 फरवरी 2022 को खैबर शिकन मिसाइल को सार्वजनिक रूप से पेश किया था। इसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने विकसित किया है।

यमन में हूती विद्रोहियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था।

इसके बाद 2015 में सऊदी अरब ने कई देशों के साथ मिलकर उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। सऊदी अरब का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को दोबारा सत्ता में लाना और हूतियों का कब्जा खत्म करना था।

इसके बाद कई वर्षों तक यमन में हवाई हमले होते रहे, लेकिन सऊदी गठबंधन हूतियों को पूरी तरह पीछे धकेलने में सफल नहीं हुआ। हूती अब भी यमन के बड़े हिस्से में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उनके हमलों का असर सऊदी अरब की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रपति भवन परिसर पर ताजा हमला क्षेत्र में जारी तनाव को और बढ़ा सकता है।

जर्मनी के बोचुम में आग से 3 भारतीयों की मौत, एक गिरफ्तार



बर्लिन — जर्मनी के बोचुम शहर में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में मंगलवार तड़के लगी भीषण आग में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। मामले की जांच कर रही पुलिस ने इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय एक व्यक्ति को शुरुआती तौर पर गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की संभावना नहीं मिली है।

पुलिस ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि मृतकों में 25 और 27 वर्ष की दो महिलाएं तथा 26 वर्षीय एक पुरुष शामिल थे। तीनों भारतीय नागरिक थे।

आग लगने की जाँच में

तकनीकी खराबी मिली

ने जर्मन सार्वजनिक प्रसारक एनडीआर के हवाले से बताया कि आग लगने से एक दिन पहले रविवार को भी किसी विवाद के सिलसिले में पुलिस को इसी इमारत में बुलाया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुलिस अधिकारी पहले भी इस आवासीय परिसर में हुई विभिन्न घटनाओं के सिलसिले

में पहुंच चुके थे।

वहीं अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक जांच की गई, जिसमें एक अग्निशमन विशेषज्ञ भी शामिल था। जांच के दौरान तकनीकी खराबी की संभावना को खारिज कर दिया गया। इसके बाद इमारत में रहने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति पर संदेह जताया गया।

पुलिस ने संदिग्ध को प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। हत्या संबंधी मामलों की जांच करने वाले विशेष पुलिस दल ने उससे पूछताछ भी की है। बोचुम अभियोजन कार्यालय के निर्देश पर मामले की आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसकी जांच के अनुसार, पहले हुई घटनाओं का मंगलवार को लगी आग से कोई संबंध नहीं पाया गया है। फिलहाल, तीनों भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में जांच जारी है। पुलिस और अभियोजन अधिकारी आग लगने की परिस्थितियों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं।

नेपाल : संसदीय सुनवाई में सरकार को झटका, दो प्रस्तावित राजदूतों के नाम सर्वसम्मति से खारिज

काठमांडू

नेपाल सरकार की ओर से सिफारिश किए गए दो प्रस्तावित राजदूत संसदीय सुनवाई की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। संसदीय सुनवाई समिति की बुधवार को हुई बैठक में सऊदी अरब के लिए प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार और मलेशिया के लिए चूडामणि खरेल के नाम सर्वसम्मति से खारिज कर दिए गए।

सुनार के खिलाफ महिला हिंसा और खरेल के खिलाफ आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों के कारण उनके नामों को अस्वीकार किया गया। थापा, जापान के लिए प्रस्तावित राजदूत ज्ञान कुमार बर्था के मामले में अतिरिक्त विवरण मिलने के बाद ही फैसला लेने का निर्णय किया गया। फिलहाल, उनके नाम पर निर्णय रोक दिया गया है।

संसदीय सुनवाई समिति के इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों विवादित नामों को सर्वसम्मति से खारिज किए जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार ने अनुचित आचरण के आरोपों से घिरे व्यक्तियों को राजदूत पद के लिए सिफारिश किया था।

समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ कर रहे हैं और समिति में इसी पार्टी का बहुमत है। इसके बावजूद विवादित नामों को सर्वसम्मति से खारिज किए जाने पर समिति के निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय

नेपाल से भारत जाने वाले यात्रियों के लिए पावर बैंक पर प्रतिबंध



काठमांडू। नेपाल से भारत जाने वाले यात्रियों को अब एक विशेष प्रकार का पावर बैंक अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नेपाल एयरलाइंस ने सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह प्रतिबंध भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सर्कुलर के आधार पर लगाया गया है। नए नियम के अनुसार, मोबिकस एमके पीबी-04 पावर बैंक को भारत से या भारत के लिए संचालित होने वाली किसी भी उड़ान में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसे यात्री अपने केबिन हैंडबैग, चेक-इन बैगेज या कार्गो में भी नहीं ले जा सकेंगे। दरअसल, इससे पहले दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी। इस घटना के बाद विमान को हैदराबाद की ओर डायवर्ट कर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी।

बच्चों का डीएनए चुने डोनर से नहीं मिला

लंदन

ब्रिटेन से उत्तरी साइप्रस में मेडिकल ट्रिज्म के तहत आईवीएफ कराने वाले कस से कम 30 परिवारों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इन परिवारों ने अपने बच्चों के लिए यूरोपीय देशों के डोनर्स चुने थे, लेकिन डीएनए टेस्ट से खुलासा हुआ है कि बच्चों का आनुवंशिक स्रोत तुर्किये और अरब देशों के लोगों से मिल रहा है।

यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब 11 बच्चों के डीएनए टेस्ट में पता चला कि वे उन स्पर्म-एग डोनर्स के नहीं हैं, जिन्हें उनके माता-पिता ने सावधानी से चुना था। माता-पिता ने फ्रांस, जर्मनी,

नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रिया जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों के पूरी तरह से जांचे-परखे और स्वस्थ डोनर्स को चुना था।

खोजी रिपोर्टों के अनुसार, इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के लाभग्रा आधे मामले अकेले डोगस आईवीएफ सेंटर से जुड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्पर्म बैंक क्रायोस इंटरनेशनल ने स्पष्ट किया है कि उसने 2016 में ही डोगस क्लिनिक को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और कभी वहां स्पर्म की आपूर्ति नहीं की।

इसके बावजूद, यह क्लिनिक सालों तक क्रायोस के साथ अपने आधिकारिक

जुड़ाव का झूठा विज्ञापन देकर संतान चाहने वाले जोड़ों को ठगता रहा। डोनर की मेडिकल हिस्ट्री, रूप-रंग, शिक्षा और शौक के आधार पर माता-पिता का चुनाव बच्चों के मानवाधिकारों से जुड़ा



था, ताकि 18 साल की उम्र में वे अपने जैविक मूल को जान सकें।

फर्जी डोनर के इस्तेमाल से बच्चों के मूलभूत मानवाधिकारों का हनन हुआ है। ब्रिटिश फर्टिलिटी सोसाइटी ने इस 30 से अधिक बच्चों के मामलों में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क, गंभीर लापरवाही और संस्थागत धोखाधड़ी कारा दिया है। उत्तरी साइप्रस, जो तुर्किये के कब्जे में है, अपने लचर कानूनों के कारण आईवीएफ ट्रोटमेंट के लिए एक लोकप्रिय लेकिन जोखिम भरा गंतव्य बन गया है।

वैश्विक फर्टिलिटी रिपोर्ट्स के अनुसार, सस्ता इलाज होने के कारण हर साल 5-8 हजार विदेशी जोड़े यहां आते हैं, और पिछले 10 वर्षों में 50,000 से 70,000 विदेशी नागरिकों ने यहां के क्लिनिकों में आईवीएफ कराया है।

इनमें बड़ी संख्या ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के लोगों की है।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा.....

रैचेल नामक एक मां का मामला इस धोखे को उजागर करता है। उन्होंने 2012 में डोगस में करीब 4.43 लाख रुपये में आईवीएफ कराया था, जिसमें उन्होंने क्रायोस वेबसाइट से एक डेनिश डोनर चुना था। क्लिनिक द्वारा मेडिकल रिपोर्ट भेजने का लगातार इनकार करने उनका शक गहराया।

अब डीएनए टेस्ट से सामने आया है कि उनका बेटा जोना बायोलाजिकल रूप से उनका पुत्र है, लेकिन चुना गया डेनिश डोनर उसका जैविक पिता नहीं है। रैचेल के अनुसार, सबसे बड़ा दुख यह है कि जोना भविष्य में अपने जैविक डोनर से संपर्क करने का मौका खो सकता है।